रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1691] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2014/भाद्र 05, 1936
No. 1691] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2014/BHADRA 05, 1936

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014

का.आ. 2169(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 359(अ), तारीख 6 फरवरी, 2014 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 6 फरवरी, 2014 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और प्रस्तावित प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, प्राप्त सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

और, सिंगबा रोडोडेनड्रोन अभयारण्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य कहा गया है) उत्तरी जिला, सिक्किम में लगभग मध्य में स्थित है और मुख्य प्रवेश स्थल फुन्ची है ;

और, अभयारण्य में सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है क्योंकि गंगटोक युमथंग मार्ग (उत्तरी सिक्किम राजमार्ग) फुन्ची से होता हुआ इस अभयारण्य से गुजरता है ;

और, दक्षिणी सीमा से निकटतम कस्बा या आवास लाचुंग है जो 8 किलोमीटर दूर है और अभयारण्य का क्षेत्र 43 वर्ग किलोमीटर है ;

और, अभयारण्य में शीतोष्ण वनों से लेकर पर्वतीय चरागाहों तक एक विस्तृत वनस्पतीय विविधता वाले सूक्ष्म जलवायु की विस्तृत रेंज है और उन्नतांशीय ढाल 3048 मीटर से लेकर 4575 मीटर तक हैं और इन विविध प्रकार के वनों में बहुत से जीव-जन्तुओं का आश्रय है ;

और, अभयारण्य का सृजन भव्य रोडोडेनड्रोन वनों के साथ ही इसके अद्वितीय जीव-जंतुओं और इसकी प्रमुख जातियों के संरक्षण के लिए किया गया है और इस अभयारण्य में रोडोडेनड्रोन नेवियम (सिक्किम का राज्य वृक्ष) प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ;

और, अभयारण्य अपने वृक्षों और झाड़ियों की अद्वितीय बहुलता के लिए जाना जाता है और अभयारण्य से रोडोडेनड्रोन की लगभग 36 जातियों को लेखबद्ध किया गया है ;

और, अभयारण्य में भू-वनस्पति जैसे प्रिमुला, पोटेन्टिला, जेंटियन, सैक्सीफ्रेग्स, पोपीज की बहुलता है और एकोनाइट, सिल्वर फर, स्प्रूस, लार्च, जूनिपर, ट्रेलिंग लिचेन सहित फेसटून्ड मैपिल बिल्कुल सामान्य हैं ;

और, भूमि, मिट्टी और इसके निवासियों की सर्द ठंड की कटुता से सुरक्षा करने वाली काई के घने गलीचे से ढकी है और अभयारण्य की प्रमुख महत्ता वन्य -जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की संख्या में होना है और इसके संश्रयों को अधिकतम संरक्षण दिया गया है ;

और, अभयारण्य में हिमालय के जीव जन्तु और वनस्पति की बहुलता है और चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार वनस्पति को पूर्व हिमालय मिश्रित शंकुधारी वन प्रकार, बर्च रोडोडेड्रोन गुल्म वन प्रकार और अल्पाइन चरागाह प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ;

और, ऊपरी भूमि में प्रमुख जातियों में अन्य के साथ-साथ अबीज डेन्सा (गोब्रे सल्ला), पीसिया स्मिथियाना (स्प्रूस), सुगा डेमोसा (हेम्लोक), बेटुला अल्नोएड्स (सोर), सेलिक्स बेबिलोनिका (वीपिंग विल्लो), सेलिक्स स्कीमेंसिस, रोडोडेनड्रोन जातियां (चिमाल), बेटुला यूटिलिस (भूपत), एकर कैपेल्ली, लेरिक्स ग्रिफिथियाना (लार्च), जूनिपेरस इंडिका, जूनिपेरस रेकुर्वा, रोडोडेनड्रोन कैम्पैनुलेटम, रोडोडेनड्रोन बारबारेटम और रोडोडेनड्रोन आर्बोरेटम और इसी प्रकार की जातियां सम्मिलित हैं ;

और, इस क्षेत्र की मुख्य जाति राज्य वृक्ष होने के कारण रोडोडेनड्रोन नेवियम है जो इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से होता है और सामान्य शाकों में कई राननकुलेसियाक्य क्रुसिफेरे और कम्पोजिटे आदि सहित प्रीमुला, ऐनेमोने, फ्रिटीलारिया, इरिस, जेन्टियाना, एरिसेमा, सोस्सूरीया है और सिक्किम रोडोडेनड्रोन नेवियम का राज्य वृक्ष इस क्षेत्र में स्थानीय है ;

और, अभयारण्य हिमालय के खुरदारों और गैलिफोरमीज जैसे सिरो, देव छगल, खल्जी फीजेंट, मोनल फीजेंट, रुधिर फीजेंट आदि के लिए उपयुक्त निवास है और इस क्षेत्र में भराल और हिमचीता जैसे पशुओं के लिए कोरिडोर भी है ;

और, क्षेत्र में पक्षी जात विविधता की बहुलता है और राज्य के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से येमिसामडोंग-सेबुला-सिंगबा-कटाओ कांप्लेक्स आता है ;

और, प्रस्तावित अधिकतर पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र समीपस्त आरक्षित वन का भाग है और यह हिम चीता, लाल पंडा, क्लाउडेड चीता, ब्लू शीप और कई उच्च उन्नतांशीय गैलिफोर्मीज के लिए महत्वपूर्ण निवास है ;

और, सिंगबा रोडोडेनड्रोन अभयारण्य के आसपास कतिपय क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों अथवा उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों के वर्गों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य में सिंगबा रोडोडेनड्रोन अभयारण्य की सीमा से पचास मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन सिंगबा रोडोडेनड्रोन अभयारण्य से 25 मीटर से लेकर 50 मीटर तक है और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार वहां पर 25 मीटर होगा जहां ढलान 45 डिग्री से अधिक है और उन स्थानों पर पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 50 मीटर होगा जहां ढलान 45 डिग्री से कम है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, पूर्व की तरफ 27° 44' 43" उत्तर अक्षांश और 88° 45' 48" पूर्व रेखांश (मानचित्र की संदर्भ बिन्दु सं0 9) ; पश्चिम की तरफ 27° 44' 51" उत्तर अक्षांश और 88° 41' 25" पूर्व रेखांश (मानचित्र की संदर्भ बिन्दु सं0 6) ; उत्तर की तरफ 27° 47' 55" उत्तर अक्षांश और 88° 44' 44" पूर्व रेखांश नचित्र की संदर्भ बिन्दु सं0 1) और दक्षिण की तरफ 27° 43' 23" उत्तर अक्षांश और 88° 44' 51" पूर्व रेखांश (मानचित्र की संदर्भ बिन्दु सं0 7) द्वारा सीमाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र छोर और विस्तार के अक्षांश और रेखांश के साथ **उपाबंध 1** के रूप में संलग्न है ।

(4) सिंगबा रोडोडेनड्रोन अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाला लाचुंग ग्राम प्रमुख बिन्दुओं पर उसके अक्षांश और रेखांश के साथ इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध 2** के रूप में संलग्न है :

(5) परंतु जोनल मास्टर प्लान में **उपाबंध 2,** राज्य सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यधीन होगा ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान--(1) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विचार और अनुमोदन के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों तथा निम्नलिखित संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी, अर्थात् :--

(i) वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंध ;

(ii) सिक्किम पुलिस ;

(iii) शहरी और आवास विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) ग्रामीण प्रबंध और विकास ;

(vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ;

(vii) लोक निर्माण विभाग ;

(viii) भू-राजस्व ; और

(ix) आपदा प्रबंध ।

IndiaCode

(2) जोनल मास्टर प्लान में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंध, जलसंग्रहण प्रबंध, भू जल प्रबंध, मृदा और आद्र संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(3) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के किस्म और प्रकार कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, चालू खनन पट्टे, झीलों और अन्य जलाशयों और उद्यमकर्ता इकाइयों का अभ्यंकन करेगा ।

(4) जोनल मास्टर प्लान के अंतर्गत, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के विनियमन के लिए ऐसे उपाय होंगे, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) इस प्रकार तैयार किया गया जोनल मास्टर प्लान क्षेत्रीय विकास योजना का सहविस्तारी होगा ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् **:**--

(1) **भूमि का उपयोग**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के क्षेत्रों में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी) की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मद सं0 12, मद सं0 25, मद सं0 26, मद सं0 30 और मद सं0 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:--

(i) वर्षा जल संचय ;

(ii) कुटीर उद्योग, जिसमें ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा जैसे गृह आवास, रोपवे, कियोस्क, फनिकुलर, आदि ; और

(v) सुरक्षा बल कैम्प :

परंतु यह और कि वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का कोई उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेख में प्रकट होने वाली किसी भी भूल का राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार एसईएसजेडएमसी के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् सुधार किया जाएगा और उक्त भूल सुधार की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त भूल सुधार के अंतर्गत इस उप पैरा के अधीन यथाउपबंधित कि सिवाए किसी भी मामले में भूमि के उपयोग का परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) **प्राकृतिक जलस्त्रोत**--सभी जलस्त्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों का प्रतिषेध करने के लिए कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन**--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप जो जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे, निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में पैरा 4 में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा जैसे गृह आवास, रोपवे, कियोस्क, फनिकुलर, आदि से संबंधित मद सं0 30 में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप के सिवाए किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा एसईएसजेडएमसी की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी मूल्यवान नैसर्गिक विरासत जैसे- सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि की पहचान की जाएगी और उनको परिरक्षित किया जाएगा तथा उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजनाएं जोनल मास्टर प्लान की भाग होंगी ।

(5) **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की रचना करेगा ।

(6) **वायु प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना की रचना करेगा ।

(7) **बहिस्त्रावों का निस्सारण :**-- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(8) **ठोस अपशिष्ट :**-- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :-

(i) ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा भारत प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरण रूप से स्वीकार्य रीति में होगा ।

(9) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना स. का.आ. 630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) **यानीय यातायात** - यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	हां	-	-	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए, सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयों का प्रतिषेध है । (ख) खनन संक्रियाएं सर्वथा, 1995 की रिट याचिका (सी) सं. 202 में टी.एन. गोडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4.8.2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21.4.2014 के आदेशों के अनुसार होंगी ।
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; (ख) संबंधित केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना ।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण के कारण उद्योगों की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नए या विद्यमान प्रदूषण उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां	-	-	
6.	होटलों और सैरगाहों की वाणिज्यिक स्थापना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किन्हीं नए या विद्यमान वाणिज्यिक जैसे होटलों और सैरगाहों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
7.	जलाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	हां	-	-	
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	-	हां	-	(क) सतही जल और भूमिगत जल का निष्कर्षण भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू उपभोग के लिए अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ;

IndiaCode

					(ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।
9.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में संबधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यधीन सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (101 किलोवाट से 2000 तक) के सिवाए, जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों का विस्तार प्रतिषिद्ध है ।
10.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का संनिर्माण ।	-	हां	-	भूमिगत केबिलिंग को बढ़ावा देना ।
11.	किए जा रहे पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन सहित स्थानीय समुदायों द्वारा कृषि और बागवानी प्रचलन ।	-	-	हां	
12.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
13.	होटलों तथा विश्रामालयों के विद्यमान परिसरों की बाड़ लगाना ।	-	हां	-	
14.	वनस्पतियों की बाड़ लगाना ।	-	-	हां	
15.	जैविक खेती ।	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	-	हां	-	ऐसे उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन उपायों के साथ किए जाएंगे, जो लागू हों ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।
18.	विदेशी जातियों का प्रवेश ।	-	हां	-	
19.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि करना।	हां	-	-	
20.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण ।	-	हां	-	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	हां	-	-	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	-	हां	-	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	-	हां	-	-
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना ।	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

25.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	-	-	हां	-
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से मिलने वाले देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान-कृषि या कृषि आधारित उद्योग, जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हों ।
27.	नए लकड़ी आधारित उद्योग ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए लकड़ी पर आधारित उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
28.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	-	हां	-	-
29.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय, जिसके अंतर्गत मद संख्या 12, मद संख्या 25, मद संख्या 30 और मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा ।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं, जैसे गृह आवास, रोपवे, कियोस्क, फनिकुलर, आदि ।	-	हां	-	
31.	सुरक्षा बलों के कैम्प ।	-	हां	-	
32.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	हां	-	-	

5. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी) के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनी, अर्थात् : --

(i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार - अध्यक्ष ;

(ii) मुख्य वन जीव वार्डन - सिक्किम सरकार - सदस्य ;

(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि, - सदस्य ;

(iv) पीसीसीएफ - सिक्किम सरकार - सदस्य ;

(v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(vi) सिक्किम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि (एक वर्ष की अवधि के लिए) - सदस्य ;

(vii) ग्रामीण प्रबंध विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(viii) गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, सिक्किम का प्रतिनिधि - सदस्य;

IndiaCode

(ix) कृषि विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि- सदस्य ;

(x) शहरी विकास और आवास विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(xi) संबंधित जिला कलेक्टर - सदस्य ;

(xii) प्रभागीय वन अधिकारी (पीए का भारसाधक) - सदस्य ;

(xiii) मुख्य वन (वन्य जीव) संरक्षक- सदस्य सचिव ।

(2) एसईएसजेडएमसी इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित एसईएसजेडएमसी द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों की, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित एसईएसजेडएमसी द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) एसईएसजेडएमसी का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उद्यान प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) एसईएसजेडएमसी विषय-दर-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) एसईएसजेडएमसी, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक किए गए अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उस वर्ष के 30 जून तक उपाबंध 3 में दिए गए प्रोफार्मा में, की गई कार्रवाई की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

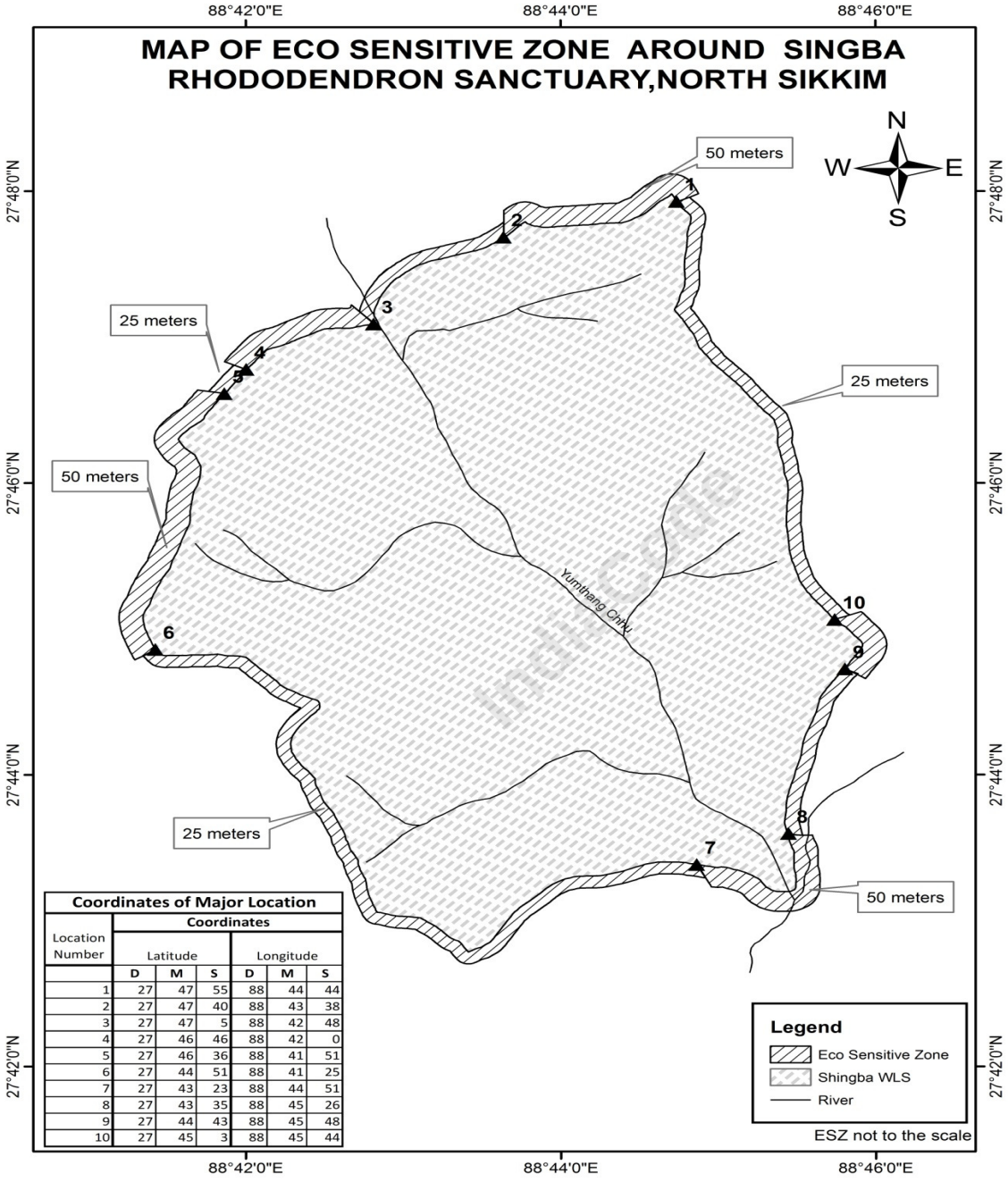
(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय-समय पर एसईएसजेडएमसी को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

[फा. सं. 25/9/2013-इएसजेड/आर ई]

डॉ. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- 1

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का, उसके छोर और विस्तार के अक्षांश और रेखांश सहित मानचित्र ।



उपाबंध-2

सिंगबा रोडोडेनड्रोन अभयारण्य, उत्तरी सिक्किम के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाला ग्राम

क्र.सं.	ग्राम का नाम	रेखांश			अक्षांश		
		डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	लाचुंग	27	43	18	88	45	6

उपाबंध-3

कार्रवाई की गई रिपोर्ट का प्रोफार्मा - राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और डाटा
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2014

S.O. 2169 (E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 359 (E), dated the 6th February, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 6th February, 2014;

And whereas, suggestions received in respect of the proposed draft notification have been considered by the Central Government;

And whereas, the Shingba Rhododendron Sanctuary (hereinafter referred to as the sanctuary) lies almost in the Centre of North District, Sikkim andthe main entry point is Phunyi.

And whereasAS, the sanctuary is approachable by road, as the Gangtok Yumthang road (North Sikkim Highway) goes through this sanctuary *via* Phunyi;

And whereas,the nearest town or habitation from the Southern boundary line is Lachung, which is 8 kilometers away and the area of the sanctuary is 43square kilometres;

And, whereas, the sanctuary possesses a wide range of microclimates, leading to a vast floral diversity right from the temperate forests to the alpine meadows and the altitudinal gradient varies from 3048 meters to 4575 meters and these diverse forest types in turn shelter a wide range of fauna;

And whereas, the sanctuary has been created to protect the magnificent rhododendron forests, along with its unique fauna and its flagship species and the *Rhododendron nevium* (the State tree of Sikkim) is found naturally in this sanctuary;

And whereas, the sanctuary is known for its unique abundance of trees and shrubs and about 36 species of rhododendrons have been recorded from the sanctuary.

And whereas,sanctuary is also rich in ground flora such as primulas, potentillas, gentians, saxifrages, poppies and aconites. Silver fir, spruce, larch, juniper, maple festooned with trailing lichens are quite common;

And whereas, the ground is covered with a dense carpet of moss protecting the soil and its inhabitants from the severity of cold winter and major significance of the sanctuary being the number of scheduled species specified in Schedule-I of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) it harbours are given maximum protection;

And whereas, the sanctuary is rich in himalayan fauna and flora and as per Champion and Seth classification, the flora may be classified as, east himalayan mixed coniferous forest type, birch-rhododendron scrub forest type and alpine pastures type;

And whereas, main species in the upper storey,*inter-alia* include, *Abies densa* (Gobre Salla), *Picea smithiana* (Spruce), *Tsuga dumosa* (Hemlock), *Betula alnoides* (Saur), *Salix babylonica* (Weeping willow), *Salix sikkimensis*, *Rhododendron* species (Chimal), *Betula utilis* (Bhujpat), *Acer campelli*, *Larix griffithiana*(Larch), *Juniperus indica, Juniperus recurva, Rhododendron campanulatum, Rhododendron barbaratum, Rhododendron arboretum and the like*.

And whereas, the key species of this area being the State tree *Rhododendron nevium* which occurs naturally in this region and common herbs are *Primula, Anemone, Fritillaria, Iris, Gentiana, Arisaema, Saussurea,* with many *Rananculaceac, Cruciferae* and *Compositae*etc.The State tree of Sikkim *Rhododendron nevium* is endemic to this region;

And whereas, the sanctuary is suitable habitat for ungulates and galliformes of the Himalayas, *viz.,*serow, goral, khalij pheasant, monal pheasant, blood pheasant etc. and the area also forms a corridor for animals like blue sheep and snow leopard;

And whereas, the area is also rich in avifaunal diversity and the Yumesamdong-Sebula-Singba-Katao complex figures prominently in the important bird areas of the State;

And whereas, the majority of the proposed Eco-sensitive area is part of a contiguous reserve forest and it is an important habitat for snow leopard, red panda, clouded leopard, blue sheep and many high altitude galliformes;

And whereas, it has become necessary to specify certain areas around the Shingba Rhododendron Sanctuary as Eco-sensitive zone and to prohibit industries or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 50 metres from the boundary of the Shingba Rhododendron Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

(i) **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—**(1)The Eco-sensitive Zone varies from 25 meters to 50 meters from the boundary of the Shingba Rhododendron Sanctuary and the extent of the said Eco-sensitive Zone shall be 25 meters, where the slope is more than 45 degree and the places where the slope is less than 45 degree, the extent of Eco-sensitive zone shall be 50 metres.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27º 44' 43" N latitude and 88º45'48"E longitude towards east (Reference point No. 9 of map); 27º44'51"N latitude and 88º41'25"E longitude towards west (Reference point No. 6 of map); 27º47'55"N latitude and 88º44'44"E longitude towards north (Reference point No.1 of map) and 27º43'23"N latitude and 88º44'51"E longitude towards south(Reference point No.7 of map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) The Lachung village falling within the Shingba Rhododendron Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith its longitudes and latitudes at prominent points is appended to this notification as **Annexure II.**

(5) Provided that the Annexure II shall be submit to confirmation by the State Government in the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—**(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, in consultation with the local people and with the following concerned State Departments, namely:—

(i) Forest, Environment and Wildlife Management;
(ii) Sikkim Police;
(iii) Urban Housing Development;
(iv) Tourism;
(v) Rural Management and Development;
(vi) Irrigation and Flood Control;
(vii) Public Works Development;
(viii) Land Revenue; and
(ix) Disaster Management.

(2) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(3) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(4) The Zonal Master Plan shall contain the measures as may be specified by the Central Government or the State Government, for regulation of activities specified under column (2) of the table specified in paragraph 4.

(5) The Zonal Master Plan so prepared shall be co-terminus with the regional development plan.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land Use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zonemay be permitted on the recommendation of the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC), and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed at item numbers 12, 25, 26, 30 and 31 specified under column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Rainwater harvesting,
(ii) Cottage industries including village artisans, etc.,
(iii) Small scale industries not causing pollution,
(iv) Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc; and
(v) Security Forces Camp:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial or industrial related development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of SESZMC, only once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(2) **Natural Springs.—**The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and strict guidelines be drawn up for the prohibition of development activities at or near these areas.

(3) **Tourism.-** The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone which shall form part of the Zonal Master Plan shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Ministry of Tourism and by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity specified at item No. 30 relating to eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. under column (2) of the Table in paragraph 4;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and be preserved and proper plan be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.—**The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(6) **Air pollution.—**TheEnvironment Department or the State Forest Department of Sikkim shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(7) **Discharge of effluents.—**Thedischarge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(8) **Solid wastes.—**Disposal of solid wastes shall be as under:—

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(9) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(10) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

IndiaCode

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibitedexcept for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

5.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	-	-	
6.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	
8.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a) The extraction of surface waterand ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
9.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited except the micro hydel power projects (Up to 100KW)or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
10.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
12.	Rain water harvesting.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
14.	Vegetative fencing			Yes	
15.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

IndiaCode

17.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.
18.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
19.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Yes	-	-	
20.	Protection of hill slopes and river banks.	-	Yes	-	
21.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
24.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
25.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
26.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment.
27.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	-	Yes	-	
29.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 12, 25, 30 and 31. In the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
30.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	-	Yes	-	
31.	Security Forces Camp		Yes		
32.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	

IndiaCode

5. **State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—**(1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee(SESZMC) for the State of Sikkim comprising of:—

(i) Chief Secretary, Government of Sikkim— Chairman

(ii) Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim— Member;

(iii) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change—Member;

(iv) PCCF, Government of Sikkim— Member;

(v) Representative of State Pollution Control Board-Member;

(vi) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim (for a term of one year) — Member;

(vii) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim — Member;

(viii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim— Member;

(ix) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim – Member;

(x) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim – Member;

(xi) Concerned District Collector—Member;

(xii) Divisional Forest Officer (In-charge of PA) — Member;

(xiii) Chief Conservator of Forest (Wild Life) — Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the SESZMC or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests and Climate Change as per proforma given in **Annexure III**.

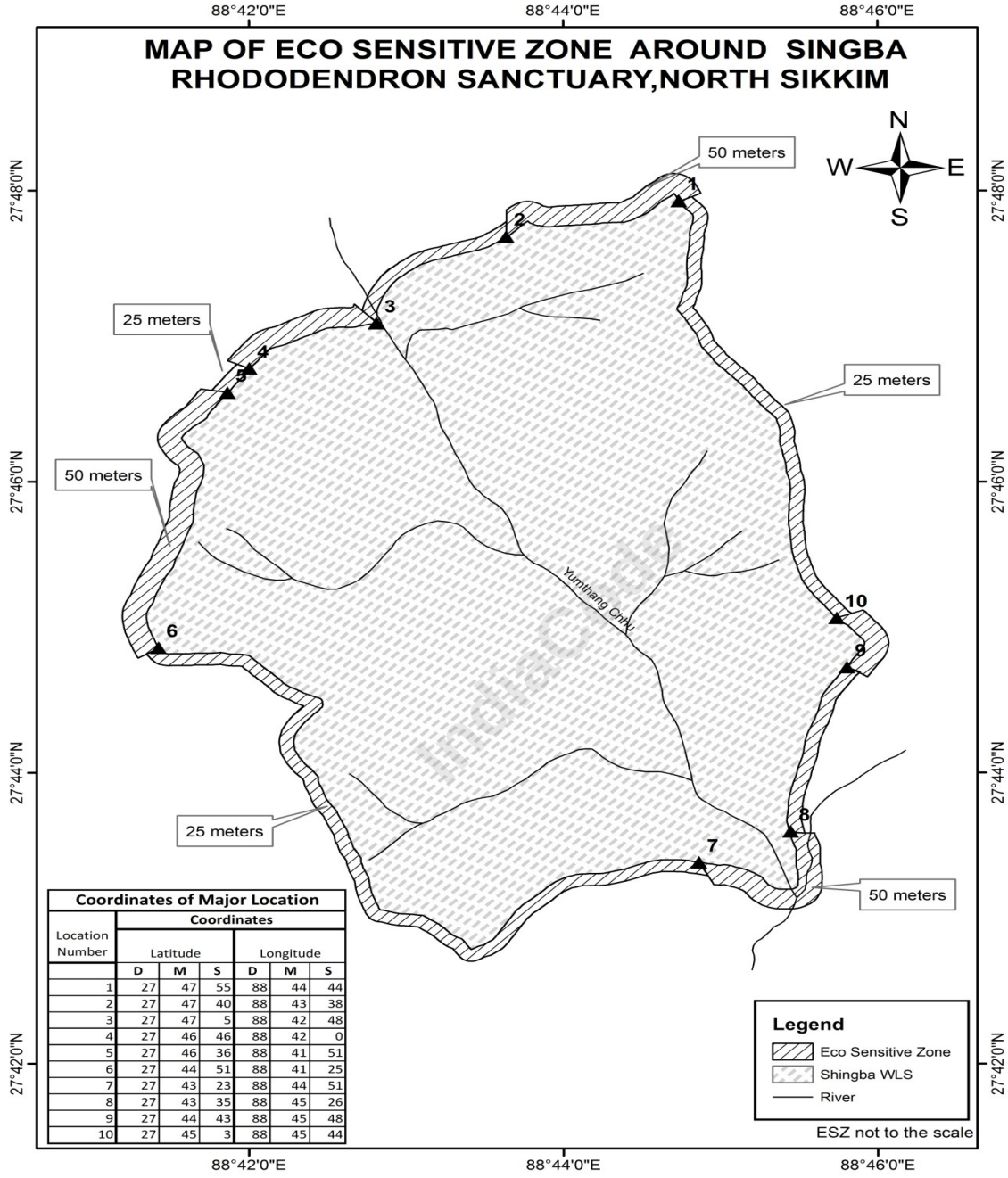
(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

[No. 25/9/2013-ESZ/RE]

Dr. SUBRAHMANYAM, Scientist-G

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Annexure II

Village falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Shingba Rhododendron Sanctuary, North Sikkim.

Sl. No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1	Lachung	27	43	18	88	45	6

Annexure III

Proforma of Action Taken Report:— State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and data of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main not worthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan (Eco-sensitive Zone-wise).
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. (Eco-sensitive Zone-wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment (EIA) Notifications, 2006 (Eco-sensitive Zone-wise).
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under EIA Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone-wise). Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986. (Eco-sensitive Zone-wise).
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.